दैनिक जागरण

विजेता कभी हौसला नहीं हारते, हौसला हारने वाले कभी नहीं जीतते

तूफान का मुकाबला

बचाव के हर संभव उपाय ही प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का बेहतर जरिया हैं, यह एक बार फिर साबित हो रहा है ओडिशा में, जो खतरनाक तीव्रता वाले तूफान फणि से दो-चार हुआ। हालांकि इस प्रचंड तूफान का असर ओडिशा के साथ-साथ आंध्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर के भी कुछ इलाकों में देखने को मिल रहा है, लेकिन यह स्पष्ट ही है कि सबसे अधिक प्रभावित ओडिशा ही है। यह तूफान कितना प्रचंड था, इसका अनुमान एक तो इससे लगता है कि ओडिशा में इसकी तीव्रता करीब दो सौ किलोमीटर प्रति घंटे की आंकी गई और दूसरे इससे कि देश के अन्य अनेक इलाकों में भी मौसम ने करवट ली। यह संतोषजनक है कि ओडिशा में पुरी शहर के तट से टकराने वाले इस तूफान के प्रचंड वेग से निपटने के लिए वे सभी उपाय किए गए जो आवश्यक थे। दस लाख से अधिक लोगों को केवल उनके घरों से निकाला ही नहीं गया, बल्कि उन्हें रहने के लिए सुरक्षित ठिकाने भी उपलब्ध कराए गए। फणि तूफान का मुकाबला करने के लिए राहत और बचाव के जो व्यापक प्रबंध किए गए उसके चलते ही कहीं अधिक कम जनहानि हुई। यह इसलिए उल्लेखनीय है कि दो दशक पहले 1999 में ओडिशा जब फणि से कहीं कम तीव्रता वाले तूफान से दो-चार हुआ था तब करीब दस हजार लोगों की मौत हुई थी। यह अच्छा हुआ कि उस तूफान के चलते हुए विनाश और फिर 2004 में सुनामी के कहर से सबक लेकर संस्थागत स्तर पर जरूरी उपाय किए गए। इन उपायों का लाभ आज पूरे देश को ही नहीं, पड़ोसी देशों को भी मिल रहा है। इन उपायों के तहत एक ओर जहां मौसम संबंधी सटीक सूचनाएं देने वाले तंत्र को दुरुस्त किया गया वहीं दूसरी ओर किसी भी तरह की आपदा से ग्रस्त लोगों के बचाव के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल यानी एनडीआरएफ का गठन किया गया। इसी तर्ज पर राज्यों ने भी अपने आपदा प्रबंधन बल गठित किए। ऐसा करना समय की मांग थी।

आज एनडीआरएफ हर तरह की आपदा की स्थिति में भरोसे का बल ही नहीं, देश की एक ताकत भी है। बीते कुछ वर्षों में इस बल ने तूफान, बाढ़ के साथ-साथ बड़ी दुर्घटनाओं में राहत और बचाव के जो कार्य किए हैं उससे एक मिसाल कायम हुई है। इस बल ने अब तक साढ़े चार लाख से अधिक लोगों को बचाने का ही काम नहीं किया है, बल्कि राहत और बचाव संबंधी तंत्र को भी सुदृढ़ किया है। जो लोग यह रोना रोते रहते हैं कि देश तरक्की नहीं कर रहा और कहीं भी हालात ठीक नहीं उन्हें एनडीआरएफ सरीखी संस्थाओं के काम-काज को देखना चाहिए। निःसंदेह इसका आकलन करने में समय लगेगा कि प्रचंड रूप धारण करने वाले फणि तूफान ने कहां कितना नुकसान पहुंचाया, लेकिन यह जानना सुखद है कि लाखों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। चूंकि ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव के चलते मौसम में अप्रत्याशित तब्दीली रह-रह कर होते रहने के आसार हैं इसलिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय एवं अन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

जंगलमहल पर जोर

पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अब कभी माओवादियों का गढ़ रहे जंगलमहल की ओर बढ़ चुका है। छठे चरण में बंगाल का जंगलमहल कहे जाने वाले पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया और बांकुड़ा जिले की छह लोकसभा सीटें एवं पूर्व मेदिनीपुर की दो सीटों पर 12 मई को वोट डाले जाएंगे। यह चरण तृणमूल के लिए काफी अहम है, क्योंकि इन आठों ही सीटों पर तृणमूल के कब्जा रहा है और 2011 एवं 2016 के विधानसभा चुनाव में जंगलमहल की सर्वाधिक सीटों पर तृणमूल को जीत मिली थी। हालांकि अब स्थिति बदल रही है। जिसका नतीजा रहा है कि आदिवासी बहुल पुरुलिया, झाड़ग्राम से लेकर पश्चिम मेदिनीपुर एवं बांकुड़ा जिले में पिछले वर्ष पंचायत चुनाव में भाजपा ने तृणमूल को कड़ी टक्कर ही नहीं दी, बल्कि कई पंचायतें छीन ली। इसीलिए इस बार भाजपा की भी नजर इस क्षेत्र पर अधिक है। यही वजह है कि भाजपा लोकसभा चुनाव के छठे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चार जनसभाएं आयोजित करने जा रही है। छह मई को तमलुक और झाड़ग्राम तथा 9 मई को बांकुड़ा और पुरुलिया में सभा होनी है। वहीं तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने भी अब जंगलमहल का रुख कर लिया है। वैसे तो शुक्रवार से ही उनकी चुनावी सभा का दौर शुरू होना था, लेकिन चक्रवात की वजह से शनिवार तक की उनकी सभी चुनावी सभाएं स्थगित हो गई हैं। वहीं पीएम मोदी की हल्दिया में पांच मई को सभा प्रस्तावित थी, लेकिन तूफान की वजह से उसे अब छह मई को कर दिया गया है। पहाड़ यानी उत्तर बंगाल, समतल यानी दक्षिण बंगाल से होते हुए अब जंगलमहल में मोदी एवं ममता के बीच जुबानी जंग होगी। भाजपा को इस बार बंगाल से काफी उम्मीद है। उसी के मद्देनजर भाजपा शीर्ष नेतृत्व यानी मोदी से लेकर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह तक ने बंगाल में पूरी ताकत लगा रखी है। अब तक सिर्फ मोदी बंगाल में 9 रैलियां कर चुके हैं और छठे चरण से पहले उनकी चार और रैलियां होगी। इतना ही नहीं बंगाल में आखिरी चरण में कोलकाता एवं आसपास के इलाकों में मतदान होना है। प्रदेश भाजपा नेतृत्व चाह रहा है कि उससे पहले मोदी और अमित शाह की बड़ी रैलियां एवं रोड शो कोलकाता में आयोजित हों।

भारत में सिर उठाता जिहादी आतंक

ब्रह्मा चेलानी

चूंकि आतंक विरोधी अभियान में भारत का ध्यान जम्मू-कश्मीर में ही केंद्रित है इसलिए जिहादियों को केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल आदि में अपना असर बढ़ाने की गुंजाइश मिल रही है

भारत जहां जम्मू-कश्मीर में आतंक की चुनौती का तोड़ निकालने की जद्दोजहद में जुटा है वहीं पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में धीरे-धीरे जिहादी ताकतें सिर उठा रही हैं। भारत लगातार बढ़ते इस खतरे की अनदेखी नहीं कर सकता है, क्योंकि आइएस ने कथित रूप से बंगाल के लिए अपने नए 'अमीर' की घोषणा कर दी है और श्रीलंका में हुए बम धमाकों ने तमिलनाडु और केरल में जेहादी ताकतों की बढ़ती भूमिका और उन्हें विदेशों से मिलने वाली मदद की ओर ध्यान खींचा है। श्रीलंका बम धमाकों के लिए जिम्मेदार नेशनल तौहीद जमात यानी एनटीजे तमिलनाडु में तेजी से फल-फूल रहे तमिलनाडु तौहीद जमात यानी टीएनटीजे का वैचारिक सहोदर ही है। सऊदी वित्तीय मदद से चल रहा टीएनटीजे कट्टर वहाबी विचारधारा का समर्थक है। मुस्लिम समुदायों का लगातार अरबीकरण हो रहा है और इसका प्रभाव बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से लेकर केरल, तमिलनाडु और श्रीलंका के पूर्वी प्रांतों तक देखा जा रहा है। सीरिया और इराक में आइएस के पराभव के बाद आतंकवाद की चुनौती और कठिन हो गई है। आतंक हमलों का प्रशिक्षण पाने वाले आइएस के ये लड़ाके सीरिया और इराक से अपने घरों को लौट रहे हैं। इससे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। ये लड़ाके बड़े आतंकी हमले करने में पारंगत हो चुके हैं। श्रीलंका के धमाके यह बताते हैं कि अज्ञात स्थानीय समूह कितनी भारी तबाही मचा सकते हैं। उन्होंने तीन प्रमुख चर्चों और तीन लक्जरी होटलों को एक साथ उड़ा दिया।

श्रीलंका आतंकी हमला वास्तव में इस बड़े खतरे को रेखांकित करता है कि सीरिया और इराक से लौटे आइएस के आंतकी कुछ वैसी ही रणनीति अपना सकते हैं जैसी अफगान युद्ध खत्म होने के बाद ओसामा बिन लादेन और उसके संगठन अल कायदा ने अपनाई थी। अल कायदा जैसे संगठनों ने एशिया, पश्चिम एशिया और पश्चिमी देशों को अपने आतंक से दहला दिया था। हालांकि आतंक का खतरा केवल सीरिया और इराक से लौटे आतंकियों से ही नहीं है। वे स्थानीय लोग भी बड़े खतरे के रूप में उभरे हैं जो अपने-अपने देश में रहकर ही हिंसा को मजहब का एक हिस्सा मानने लगे हैं। आतंक का महिमामंडन करने वाली ऐसी ताकतें दिनोंदिन मजूबत होती जा रही हैं। मौजूदा आम चुनावों में द्रमुक और कुछ अन्य स्थानीय दलों ने खुलेआम उस टीएनटीजे की पैरवी की है जिसने श्रीलंका में तौहीद जमात को जड़ें जमाने में मदद की।

बांग्लादेश ने 2016 में ढाका के एक कैफे में धमाकों के लिए पाकिस्तान की कुख्यात एजेंसी आइएसआइ को जिम्मेदार बताते हुए कहा था कि हमले के लिए उसने कैसे एक बांग्लादेशी संगठन को अपना मोहरा बनाया। यही काम श्रीलंकाई एनटीजे ने आइएसआइ के पिट्ठू लश्करे ए तैयबा के साथ मिलकर किया। आइएसआइ और लश्कर ने श्रीलंका में अपने संयुक्त परिचालन के साथ ही भारत में टीएनटीजे कार्यकर्ताओं को भी साथ जोड़ लिया है। श्रीलंका में आत्मघाती हमले में मारा गया एनटीजे का मुखिया जहारन हाशिम भगोड़े और विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के जहरीले धार्मिक भाषणों से प्रेरित था। हाशिम को दक्षिण भारत से वित्तीय मदद मिलने की खबरें भी सामने आई हैं।

अवधेश राजपूत

बम धमाकों को लेकर श्रीलंका को खुफिया जानकारी देने के बावजूद अपनी सरहदों के भीतर जिहादी ताकतों के खिलाफ रणनीति बनाने में भारत का रवैया बहुत सुस्त रहा है। भारत ने ढाका हमले के बाद ही जाकिर नाइक पर तब प्रतिबंध लगाया जब बांग्लादेश ने उस पर कार्रवाई की मांग की। आज नाइक मलेशिया में पनाह लिए हुए है, फिर भी भारत ने मलेशिया के साथ कोई कड़ाई नहीं की है। उससे पाम ऑयल का आयात भी नहीं घटाया है। मलेशिया को इसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी है कि उसने एक भारतीय भगोड़े को आश्रय दिया हुआ है।

एक समय जैसे अल-कायदा के समक्ष अपना अस्तित्व और प्रासंगिकता बनाए रखने की चुनौती उत्पन्न हो गई थी कुछ वैसे ही संकट से इस समय आइएस गुजर रहा है। यही वजह है कि वह उन इलाकों में भी आतंकी घटनाओं की जिम्मेदारी ले रहा है जहां उसकी खास मौजूदगी नहीं। श्रीलंका हमले में सीधे आइएस का हाथ होने के बजाय संभव है कि आइएस की कट्टर वहाबी विचारधारा से प्रभावित लोगों ने हमले को अंजाम दिया हो। आत्मघाती हमलावर हफ्तों नहीं, बल्कि महीनों में तैयार होता है। ऐसे में यह अटकल तार्किक नहीं लगती कि श्रीलंका हमला क्राइस्टचर्च हमले का बदला लेने के लिए किया गया। श्रीलंका के एक मंत्री ने पहले यही बयान दिया था, लेकिन बाद में श्रीलंकाई प्रधानमंत्री ने उसे खारिज कर दिया। आतंकी हमला करने वाले के परिवार को हिरासत में लेकर पूछताछ करना आतंक के खिलाफ अभियान में एक वैश्विक चलन है। श्रीलंका में भी आतंकियों की पहचान जाहिर होते ही उनके माता-पिता सहित अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ पूछताछ शुरू हो गई। अमेरिका भी यही करता है, लेकिन भारत में अलग ही दस्तूर है। पुलवामा हमला के लिए जिम्मेदार आतंकी के परिवार को न केवल खुला रखा गया, बल्कि उन्हें मीडिया से बातचीत करते भी देखा गया। वे हमले को वाजिब ठहराते भी दिखे। प्रचार आतंक की प्राणवायु है, क्योंकि इसके माध्यम से वे खौफ जताने और ताकत दिखाने का काम करते हैं। अफसोस की बात यह है कि अमेरिका की तरह भारत में आतंकी मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग के नियमों का अभाव है। भारतीय पत्रकार आतंकियों के लिए दुष्प्रचार करते हैं जैसे पुलवामा मामले में हमलावर के परिवार द्वारा किए गए इस दावे को उभारा गया कि सैन्य बलों की प्रताड़ना से उनका लड़का आतंकी बन गया। परिवार ने यह नहीं बताया कि उनका लड़का लश्कर को मदद पहुंचाने के मामले में चार बार पहले भी जम्मू-कश्मीर पुलिस के निशाने पर आ चुका था। हर बार वह संदेह के लाभ में छूट जाता था।

जेहादी आतंकवाद का वहाबी विचारधारा से गहरा जुड़ाव है। इस हिंसक एवं असहिष्णु धारा को सऊदी अरब सहित कई देश वित्त पोषित कर रहे हैं। वहाबी कट्टरता जहां आतंकवाद की वैचारिक धुरी है वहीं आइएस, अल-कायदा, तालिबान, लश्कर ए तैयबा और बोको हराम उस आतंक को अमली जामा पहनाने वाली कड़ियां। श्रीलंका की ही तरह तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जिहादी खतरे की कड़ी वहाबी विचारधारा के प्रसार के साथ जुड़ी है। अगर इस जेहादी खतरे से निपटा नहीं गया तो यह भारत में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है। चूंकि आतंक विरोधी अभियान में भारत का ध्यान मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर में ही केंद्रित है इसलिए जिहादियों को केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में प्रभाव बढ़ाने की गुंजाइश मिल जाती है। भारत को इस सिर उठाते खतरे के प्रति सचेत होने की जरूरत है। उसे हिंसा और नफरत फैलाने वालों पर शिकंजा कसना होगा। इसके साथ ही सऊदी और खाड़ी के अन्य देशों से आने वाले पैसों पर भी निगरानी रखनी होगी ताकि उस स्रोत पर शिकंजा कसा जा सके जिससे आतंकवाद फलता-फूलता है।

(लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)

response@jagran.com

अन्याय के खिलाफ कठिन लड़ाई

सुभाषिनी अली सहगल

अत्याचार के शिकार पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई बहुत कठिन होती है, खासकर तब और जब आरोपी कथित धर्मगुरु हो

एक बड़ी खबर जो चुनावी कोलाहल में दब गई कि इसी 26 अप्रैल को आसाराम बापू के बेटे नारायण साई को सूरत की अदालत ने दुष्कर्म का दोषी पाया। 30 अप्रैल को उसे आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई। 2013 में दो बहनों ने बाप-बेटे, दोनों के खिलाफ लगातार दुष्कर्म और यौन-उत्पीड़न करने का मुकदमा दायर किया था। आसाराम बापू जोधपुर जेल में तब कैद किए गए थे जब एक नाबालिग बच्ची ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया था। 2018 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वह बच्ची और दोनों बहनें आसाराम के आश्रम और बोर्डिंग में रहती थीं। तीनों के परिवारजन आसाराम के भक्त थे। पीड़ितों ने आश्रम में काम करने वाली 'सेविकाएं' और आसाराम की पत्नी और बेटी पर आरोप लगाया था कि वे लड़कियों पर दबाव बनाती थीं, उन्हें धमकियां देती थीं और उन्हें आसाराम की कुटिया तक जाने के लिए मजबूर करती थीं। जोधपुर की अदालत ने दो सेविकाओं को भी 10-10 साल की सजा दी।

यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म की शिकार तमाम पीड़िताओं के लिए न्याय की लड़ाई बहुत कठिन होती है और जब आरोपी 'धर्म-गुरु' हो, जिसके पास अपार धन के अतिरिक्त बहुत ही प्रभावशाली भक्त हों जिनमें राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की गिनती हो तो यह लड़ाई असंभव सी हो जाती है। यही नहीं, इन 'धर्म गुरुओं' के बहुत सारे सहधर्मी उनके निर्दोष होने की बात को इस तरह से प्रचारित करते हैं जैसे उनके दोषी साबित हो जाने से वे खुद भी उस दोष में भागीदार हो जाएंगे। विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं जिन पर यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के आरोप लगाए गए हैं, के मामलों में इस तरह का व्यवहार देखा जा सकता है। अक्सर पीड़ित महिला भी आरोपी धर्मगुरु के ही धर्म को मानने वाली होती है, लेकिन उसके साथ सहधर्मियों की हमदर्दी नहीं जुड़ती। उसकी पीड़ा में वे अपनी पीड़ा को संबद्ध नहीं करते। स्पष्ट है कि ऐसे में न्याय की लड़ाई असहनीय कष्टपूर्ण हो जाती है।

इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आसाराम बापू पर आरोप लगाने वाली 16 वर्षीय बच्ची से 37 दिन तक अदालत में लगातार पूछताछ के बाद ही मुकदमे की कार्यवाही शुरू की गई। देश के सबसे बड़े वकील आसाराम की ओर से खड़े हुए। उन्होंने लड़की को बदचलन, पागल, झूठी, लालची आदि साबित करने की भरसक कोशिश की। मुकदमे के दौरान नौ गवाहों पर जानलेवा हमले हुए जिनमें से तीन मर गए। पीड़ित बच्ची ने एक पत्रकार से कहा कि ऐसा लगता है कि आसाराम नहीं, वह कैद है। वह कहीं जा नहीं सकती, किसी से बात कर नहीं सकती, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बात पर अटल रही। 12 बार जमानत की अर्जी लगाने के बाद आसाराम को आखिर सजा हो ही गई। अब उसके बेटे को भी सजा हो गई है।

ऐसा नहीं कि अदालत के फैसलों के बाद सभी लोग आसाराम को गुनाहगार मानने लगे हों। केवल उनके भक्त ही नहीं, बल्कि उनके तमाम सहधर्मी भी उन्हें साजिश का शिकार मानते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि पिछले कई सालों में बच्ची के परिवार पर क्या गुजरी है। उन गवाहों के अनाथ बच्चों का क्या हाल है जो अब नहीं रहे। सोशल मीडिया पर आज भी आसाराम बापू को निर्दोष मानने और बताने वाले लोग मौजूद हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति राम-रहीम और रामपाल के मामले में भी देखने को मिलती है।

आश्चर्य की बात तो यह है कि बड़े-बड़े लोग जो समाज की बुराइयों को दूर करने का दावा करते हैं वे भी आसाराम और उन अन्य तथाकथित संतों को निर्दोष होने की रट लगाए हुए हैं जिन्हें अदालत की ओर सजा सुनाई जा चुकी है। आजकल सुर्खियों में रहने वाली प्रज्ञा ठाकुर भी इनमें से एक हैं। उनका कहना है कि आसाराम देवता-तुल्य हैं, धर्म-गुरु हैं इसलिए ऐसा कर नहीं सकते जैसे कि उन पर आरोप है। क्या उनका ऐसा कहना वास्तव में आश्चर्यजनक है? दरअसल उनका ऐसा कहना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस मानसिकता के तहत वह आसाराम को निर्दोष बता रही हैं उसी मानसिकता की वह स्वयं सबसे बड़ी लाभार्थी हैं।

जिस तरह से आसाराम को धर्मगुरु और भगवान मानने वालों के अलावा उनके सहधर्मी उनको निर्दोष नहीं मानते, बल्कि उनको दोषी ठहराने वालों पर आक्रामक हो जाते हैं उसी मानसिकता का सबसे अधिक लाभ प्रज्ञा ठाकुर को मिल रहा है। जब आसाराम के मुकदमे की खबरें छपती थीं तो उनके आंसू, उनका चेहरा, उनके बयान देखने-सुनने को मिलते थे। उनके खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने वालों की पीड़ा, बेबसी नहीं दिखती थी। प्रज्ञा ठाकुर के भी आंसू, आरोप, श्राप दिख रहे हैं। उन पर हिंसक हमलों का आरोप लगाने वाले अवाक हैं। ऐसा होता रहेगा तो जुल्म और अन्याय तो बढ़ेगा ही, उसके विरुद्ध लड़ाई और भी मुश्किल-शायद नामुमकिन हो जाएगी।

(लेखिका लोकसभा की पूर्व सदस्य हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

शून्यता

ध्यान ऐसी विलक्षण क्रिया है जो व्यक्ति का व्यक्ति की वास्तविकता से परिचय कराती है। साधारणतया व्यक्ति अपनी पहचान को अपने नाम, अपने परिवार अपने स्वभाव और विचारों एवं चाहत तक ही सीमित किए हुए है और इन्हीं को लपेटे हुए वह इस संसार में सुख एवं दुख का अनुभव करता रहता है। अधिकांश व्यक्ति अपनी असली पहचान को तलाशने का प्रयास ही नहीं करते हैं। किसी भी व्यक्ति की असली पहचान सारे समय इन सांसारिक अनुभवों को प्राप्त करते हुए किया जाना संभव ही नहीं है। उसे यदि अपना वास्तविक परिचय जानना है तो प्रतिदिन कुछ क्षणों के लिए समस्त सांसारिक क्रियाकलापों और विचारों से विरक्त होकर मस्तिष्क को वहां ले जाने का प्रयास करना होगा जहां उसे केवल शून्यता अनुभव हो रही हो। इसी क्रिया का नाम ध्यान है, जो हमें विचारों से मुक्त करके शून्यता की ओर ले जाती है।

वास्तव में विचारों की शून्यता की स्थिति ही हमारा वास्तविक स्वरूप है जहां से हम अपनी वास्तविक पहचान को अनुभव कर पाते हैं। इस संसार में हमारी जो पहचान है, वह हमारे सांसारिक नाम और इस नाम के आधार पर अर्जित यश या अपयश के आधार पर होती है, किंतु गहराइयों में जाकर हम अपनी आत्मा के प्रकाश द्वारा उस जगह को देखने में सक्षम हो जाते हैं जहां से हमें इस संसार में भेजा गया है। इसे देखकर यही अहसास होता है कि हमारा वास्तविक घर तो यही है जहां हमें घूम फिर कर पुनः लौट कर आना है। यह गहराई जब अनुभव होती है उस समय मस्तिष्क में न तो कोई विचार होता है न वासना और न ही कोई अहंकार। यहां पहुंचकर हमारा परिचय हमारे काल्पनिक मैं से नहीं रह जाता है। यहां यही अनुभव होता है जैसे मस्तिष्क की समस्त परतें खुल गई हों और टकराने के लिए कुछ भी शेष न बचा हो। यदि कुछ बचा रहता है तो वह केवल शून्यता ही होती है जो हमारा स्वयं का परिचय होता है। हम अपने स्वयं को अपने मन में उठती विचारों की तरंगों में नहीं ढूंढ़ सकते हैं। शून्यता वहीं होती है जहां सब कुछ समाया रहता है। इस शून्यता को जब उखाड़ने का प्रयास किया जाता है तब इसमें ज्ञान की परतें खुलती जाती हैं, जो कि असीम हैं। इसलिए हर एक को इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए।

वीके जायसवाल

तथ्य-कथ्य | बुजुर्ग आबादी का बढ़ता हिस्सा

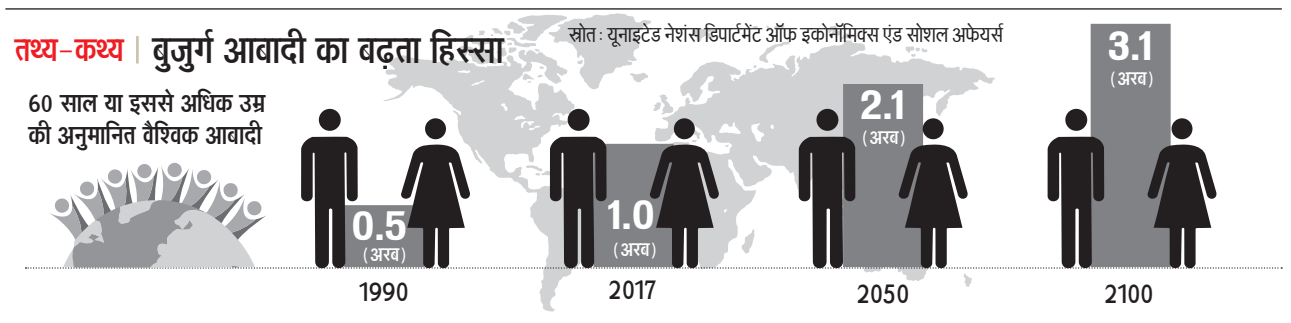

मवेशियों के स्वास्थ्य का सवाल

रीता सिंह

अगर लोगों में मवेशियों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़े तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान बढ़ सकता है

भारत में मवेशियों को धन और शक्ति की संज्ञा दी गई है। मशीनी युग के बावजूद भी विभिन्न कृषि कार्यों में इनकी उपयोगिता बरकरार है। हल चलाने से लेकर सिंचाई करने, बोझ ढोने, गन्ना पेरने, अनाज से भूसे को अलग करने, कृषि उपज को मंडी तक ले जाने आदि कई कृषि कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भूमिहीन, लघु एवं सीमांत किसान बड़े पैमाने पर पशुपालन करते हैं जिससे उन्हें अच्छी आमदनी होती है, लेकिन यह चिंताजनक है कि देश में इन घरेलू पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशीलता की भारी कमी है, जिसके कारण उनकी तादाद में लगातार कमी आ रही है। गौर करें 1947 से लेकर 1992 तक मवेशियों की संख्या में इजाफा हुआ, लेकिन उसके बाद उनकी संख्या में आनुपातिक गिरावट आई है।

एक आंकड़ें के अनुसार 1951 में मवेशियों की संख्या 155.3 लाख थी जो वर्ष 1992 में बढ़कर 204.58 लाख हो गई, लेकिन 1997 में यह संख्या घटकर 198.88 और वर्ष 2003 में 185.18 लाख तक रह गई। वर्ष 2017 में इनकी संख्या में जरूर मामूली इजाफा हुआ, लेकिन यह संतोषजनक नहीं है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार एवं कुछ राज्य सरकारें पशुओं के स्वास्थ्य और संरक्षण को लेकर चिंतित हैं। गत वर्ष केंद्र सरकार ने देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की। इस योजना के तहत बड़े शहरों के आसपास लगभग एक हजार गायों को एक साथ रखा जा सकेगा। इनमें 60 फीसद दूध देने वाली देसी गायों और 40 फीसद बिना दूध देने वाली गायें होंगी। इन गायों का पालन-पोषण वैज्ञानिक ढंग से किया जाएगा तथा समय-समय पर इनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। साथ ही इन गायों के गोबर से जैविक खाद तैयार किया जाएगा। गोकुल ग्रामों में बायो गैस स्थापित किए जाने की भी योजना है जिससे कि बिजली की सुविधा मिल सके। इसके अलावा सरकार ने जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर समेकित रूप से देसी नस्ल के पशुओं के विकास के लिए कामधेनु प्रजनन केंद्र की स्थापना की भी योजना बनाई है। निश्चित रूप से इस योजना से मवेशियों का संरक्षण होगा और उनकी तादाद बढ़ेगी। अच्छी बात यह है कि कुछ राज्य सरकारें भी इस दिशा में पर्याप्त कदम उठा रही हैं। देसी गायों को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गोवा और ओडिशा जैसे राज्यों में सकारात्मक पहल की जा रही है। यूपी सरकार द्वारा पशुपालकों को पशुओं की सेहत की निगरानी के लिए पशु स्वास्थ्य कार्ड दिया जा रहा है। इसके साथ ही पशु के शरीर में विशिष्ट पहचान संख्या वाले टैग लगाए जाने की भी योजना है। निःसंदेह इस पहल से पशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी हो सकेगी और उसका लाभ पशुपालाकों एवं देश, दोनों को मिलेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का कितना महत्व है इसे इसी से समझा जा सकता है कि सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का 28-30 प्रतिशत हिस्सा है। अगर लोगों में पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़े तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान बढ़ सकता है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

आतंक के विरुद्ध चीन का निर्णायक कदम

आतंक के खिलाफ बड़ी सफलता शीर्षक वाले अपने लेख में विवेक काटजू ने भले ही चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र के समक्ष लिए गए निर्णय को उसकी अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि बचाने वाला कदम बताया है, लेकिन इस संदर्भ में यह भी एक तथ्य है कि अब चीन भारत के हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। डोकलाम विवाद पर मोदी सरकार के कड़े रुख को चीन अभी भूला नहीं है। पुलवामा अटैक करने वाला आतंकी सरगना मसूद अजहर भारत का दुश्मन नंबर वन है, इस बात को चीन बखूबी जानता था, लेकिन पाकिस्तान से अपने हितों को साधने के लिए वह संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर जैसे कुख्यात आतंकवादी पर सकारात्मक निर्णय नहीं ले पा रहा था, पर भारत के कूटनीतिक दबाव से चीन पस्त हो गया और अंततोगत्वा उसे मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने में अपनी सहमति देनी पड़ी। अंतरराष्ट्रीय दबाव में लिए गए चीन के इस निर्णायक कदम को जिहादी आतंकवाद पर करारी चोट के रूप में देखा जाना चाहिए। अब पाकिस्तान को छोड़कर विश्व का कोई भी देश दाऊद, हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे कुख्यात आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाला नहीं है। पाकिस्तान को भी संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और चाहे दिखावे के लिए ही सही, लेकिन उसे अपने यहां पल रहे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी मसूद अजहर के विरुद्ध कार्रवाई करनी ही पड़ेगी और यही भारत की जीत है।

pandeyvp1960@gmail.com

बधाई में भी राजनीति

चुनावी माहौल में सभी दल देश में घटने वाले प्रत्येक घटनाक्रम को अपने राजनीतिक नफे-नुकसान के नजरिये से । अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ना मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय स खबर के आते ही कांग्रेस ने गर्व स- ने 2009 में सबसे पहले मसूद को राने का प्रस्ताव रखा था। जब भारत की जीत का श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्र सकता है तो आज मसूद अजहर को राने के प्रयासों में मिली सफलता प ों नहीं हो सकते? यहां कांग्रेस से ए ना चाहिए कि वह चीन के एक बार ों तक शांत क्यों रही। यूपीए सरका हीं किए। यदि प्रस्ताव की पहल कर को देने में कांग्रेस को संकोच नहीं है फलता का श्रेय एनडीए सरकार को द ाई? कांग्रेस के अन्य कई नेताओं श यादव ने भी राजनयिकों को बध ी विपक्षी नेता के मुंह से प्रधानमंत्री क द तक नहीं निकला। जब मसूद के दल सहमत हैं तो फिर उसके वैश्विक बधाई देने में भी राजनीतिक नफे-न हां तक उचित है?

संजय कौ

की कूटनीतिक जीत

जार के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा प मास्टरमाइंड मसूद अजहर को वैश्वि घोषित कर दिया। आखिरकार चीन को भी भारत की कूटनीति के आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। हालांकि यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था, परंतु चीन बार-बार यूएन में अपने वीटो का दुरुपयोग कर ऐसा होने नहीं देता था। यह भारत र की कूटनीतिक सफलता ही है जिसकी वजह से अंततः अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया।

shubhamgupta121@gmail.com

कियों के अड्डे

ाल बम ब्लास्ट के बाद श्रीलंका सरकार द्वारा वादी गुटों और सगठनों पर कड़ी करवाई की जा रही ातंकवाद के तार पाकिस्तान एवं अन्य आइएसआइ वादी संघटनों से जुड़े होने के सबूत भी मिले हैं। हमले द सुरक्षा और आतंकवादियों पर कर्रवाई से कुछ समय ए आतंकवादी संगठनों को रोका जा सकता है, लेकिन वाद को समूल नष्ट करने के लिए विश्व के सभी देशों जुट होकर आतंकवादियों को आर्थिक और सामाजिक ं नष्ट करना होगा।

skcbe@gmail.com

ा स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र ोजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: om

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशि हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपाद आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त वि mailb